आर्थिक संसाधन

अनुलग्नक–4

परिवहन विभाग

- वर्ष 2006–07 में परिवहन विभाग का राजस्व संग्रह 202.14 करोड़ रू0 था जो वर्ष 2010–11 में बढ़कर 444.1 करोड़ रू0 हो गया। वर्ष 2011–12 में जनवरी' 2012 तक 440.67 करोड़ रू0 संग्रह हो चुका है। वर्ष 2007–08 से परिवहन विभाग के राजस्व संग्रह में औसतन 21 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2012–13 का लक्ष्य 644.40 करोड़ निर्धारित है।
- वर्त्तमान में कुल 293 बसें लोक निजी भागीदारी अधीन परिचालित हो रही है। 300 अन्य नई बसों का जिला मुख्यालय के बीच परिचालन का निर्णय लिया जा चुका है। जिसके लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा प्रत्येक बस हेतु 5.00 लाख रू0 की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
- वाहन कर का भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से वर्ष 2012–13 के प्रारंभ में उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिससे कर का भुगतान नेट–बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/प्री–पेड–कार्ड/डेविट–कार्ड इत्यादि के माध्यम से बिना जिला परिवहन कार्यालय गये भुगतान कर सकेंगे ।

खान एवं भूतत्व विभाग

- राज्य विभाजन के पश्चात् सीमित खनिज संसाधन से सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में उत्तरोत्तरी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2007–08 में 146.34 करोड़ रू0 राजस्व संग्रह हुआ था जबकि वहीं वर्ष 2011–12 में 375.00 करोड़ रूपये राजस्व संग्रह संभावित है।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

निबंधन प्रक्षेत्र–

- जाली कोर्ट फीस स्टाम्पों की बिक्री पर कारगर रोक के उद्देश्य से पटना उच्च न्यायालय में फ्रैंकिंग मशीन द्वारा कोर्ट फी स्टाम्पों की बिक्री की व्यवस्था लागू की गयी है। इसके अतिरिक्त 29 जिला एवं सत्र न्यायालयों एवं 04 अनुमंडल व्यवहार न्यायालयों में जिला स्कोर के माध्यम से फ्रैंकिंग मशीन से कोर्ट फी स्टाम्प की बिक्री प्रारंभ की गयी है तथा शेष बचे हुए न्यायालयों में उक्त कार्रवाई की जा रही है।
- वर्ष 2010–11 में निर्धारित लक्ष्य 1,215 करोड़ के विरूद्ध 1,246 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की गयी। वर्ष 2011–12 में निर्धारित लक्ष्य 1,600करोड़ के विरूद्ध जनवरी' 2012 तक 1,156.21 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2012–13 तक लक्ष्य 1856 करोड़ निर्धारित किया गया है।
- भूमि का खेसरावार वर्गीकरण तथा सभी तरह के पट्टों के अनिवार्य निबंधन की व्यवस्था की जा रही है, जिसके क्रमशः 100/– करोड़ रू0 एवं 2 करोड़ रू0 प्रति वर्ष राजस्व वृद्धि संभावित है।
- राजस्व संवर्द्धण के उद्देश्य से **GIS based Visual Minimum Value Register** तैयार कराया जा रहा है, ताकि भूमि का एम0वी0आर0 में आकलित मूल्य तथा बाजार मूल्य के अंतर को कम किया जा सके।
- वर्ष 1996 से 2005–06 के मैनुअल निबंधन अभिलेखों के डिजिटाईजेशन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जो वेब आधारित होगा। इससे भूमि/सम्पत्ति पर ऋण अवभार के संबंध में ऑनलाईन जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

उत्पाद एवं मद्य निषेध प्रक्षेत्र–

- वित्तीय वर्ष 2012–13 में उत्पाद नीति में संशोधन करते हुए देशी शराब को सैचेट के स्थान पर बोतल (होलोग्राम स्टीकर) में बेचने की व्यवस्था की जाएगी। इस व्यवस्था से शराब में मिलावट को रोका जा सकेगा।
- वर्ष 2010–11 में 5400 दुकानों की बन्दोबस्ती हुई थी। वर्ष 2011–12 में दुकानों की संख्या में वृद्धि नहीं की गयी। वर्ष 2012–13 में भी 2010–11 में जितनी दुकानों थी उसी संख्या तक सीमित रखा जाएगा।